भारतीय अर्थव्यवस्था

(भाग–1)

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष: 011-47532596, 87501 87501

Web: www.drishtiias.com
E-mail : drishtiacademy@gmail.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिए निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

अर्थव्यवस्था : एक परिचय
(Economy : An Introduction)

अर्थव्यवस्था क्या है? *(What is Economy?)*

किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति (Socio-economic Conditions) में सुधार करने के उद्देश्य से, उपलब्ध संसाधनों (Available Resources) का समुचित नियोजन (Appropriate Planning) करते हुए अर्थ (Money) को केन्द्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही अर्थव्यवस्था (Economy) कहलाती है। वास्तव में 'अर्थव्यवस्था' शब्द अधूरा ही रहेगा जब तक कि इसके आगे किसी देश या किसी क्षेत्र विशेष का नाम न जोड़ा जाए, जैसे- भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विकासशील विश्व (Developing World) की अर्थव्यवस्था इत्यादि। अर्थव्यवस्था किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थशास्त्र (Economics) का गतिशील (Dynamic) चित्र है जो किसी विशेष अवधि तक ही सीमित होता है। यदि हम कहते हैं— 'समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था' तो इसका तात्पर्य होता है— वर्तमान समय में भारत की सभी आर्थिक गतिविधियों का वर्णन।

'अर्थव्यवस्था' अर्थशास्त्र में व्यापक रूप से प्रयोग होने वाली वह अवधारणा है, जिसका अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में प्रचलित आर्थिक क्रियाओं की प्रकृति एवं उनके स्तर से होता है। वह क्षेत्र चाहे तो एक गाँव, एक ज़िला, एक राज्य अथवा संपूर्ण देश हो सकता है। आर्थिक क्रिया में उत्पादन (Production), उपभोग (Consumption), निवेश (Investment) तथा विनिमय (Exchange) को शामिल किया जाता है। उत्पादन (Production) का अर्थ आगतों (Inputs) या कारकों (Factors) को उत्पाद में बदलना है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करना ही उपभोग (Consumption) है। निवेश (Investment) से अभिप्राय उत्पादन आगे बढ़ाने के लिये वस्तुओं, जैसे- भवन, मशीनें आदि का प्रयोग करना है, जबकि विनिमय (Exchange) से अभिप्राय वस्तुओं और सेवाओं के क्रय एवं विक्रय से है।

अर्थव्यवस्था के प्रकार *(Types of Economy)*

अर्थव्यवस्था के प्रकारों पर विवाद की शुरुआत एडम स्मिथ की पुस्तक 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' (The Wealth of Nations) से मानी जाती है। समकालीन विश्व में अर्थव्यवस्था के मूलत: तीन प्रकार अस्तित्व में हैं, जो निम्नलिखित हैं-

पूंजीवादी अर्थव्यवस्था/बाज़ार अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy/Market Economy): ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनमें आर्थिक क्रियाओं को बाज़ार शक्तियों (Market Forces) पर छोड़ दिया जाता है। अत: उत्पादक उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिये स्वतंत्र होता है जिनकी मांग अधिक हो, ताकि वह अधिकतम लाभ कमा सके। इसी प्रकार उपभोक्ता भी अपने चयन एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं (Goods) एवं सेवाओं (Services) को खरीदने के लिये स्वतंत्र होता है, ताकि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। किसे, क्या और कितना उत्पादन तथा उपभोग करना है, इस संदर्भ में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता।

बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र अंतर्क्रियाओं से तात्पर्य सरकार के हस्तक्षेप के बिना मांग एवं पूर्ति शक्तियों को स्वतंत्र अंतर्क्रिया करने के लिये छोड़ देने से होता है। वस्तुओं (Goods) एवं सेवाओं (Services) की कीमत पूर्ति (Supply) तथा मांग (Demand) शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है।

समाजवादी अर्थव्यवस्था/केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाएँ (Socialist Economy/Central Planned Economy): ये ऐसी अर्थव्यवस्थाएँ हैं जिनमें आर्थिक क्रियाओं का निर्धारण या दिशा-निर्देशन किसी केंद्रीय अधिकारी (Central Authority) या सरकार द्वारा होता है। केंद्रीय अधिकारी या सरकार ही यह निर्णय लेती है कि वस्तुओं तथा सेवाओं का कितना उत्पादन किया जाए कि लोगों द्वारा उपभोग किये जाने के लिये पर्याप्त हो। आर्थिक दृष्टिकोण से, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था (Free Economy) नहीं है, जबकि बाज़ार अर्थव्यवस्था निश्चय ही एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है।

मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy): ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बाज़ार अर्थव्यवस्था तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था/समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों की विशेषताओं को दर्शाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं को बाज़ार शक्तियों की स्वतंत्र अन्तर्क्रिया पर छोड़ दिया जाता है, परन्तु इसके साथ-साथ सरकार अपना नियंत्रण भी बनाए रखती है ताकि उत्पादन (Production), उपभोग (Consumption) तथा अन्य आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित किया जा सके। यहाँ सरकार आर्थिक और सामाजिक न्याय की स्थापना के लिये आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करती है।

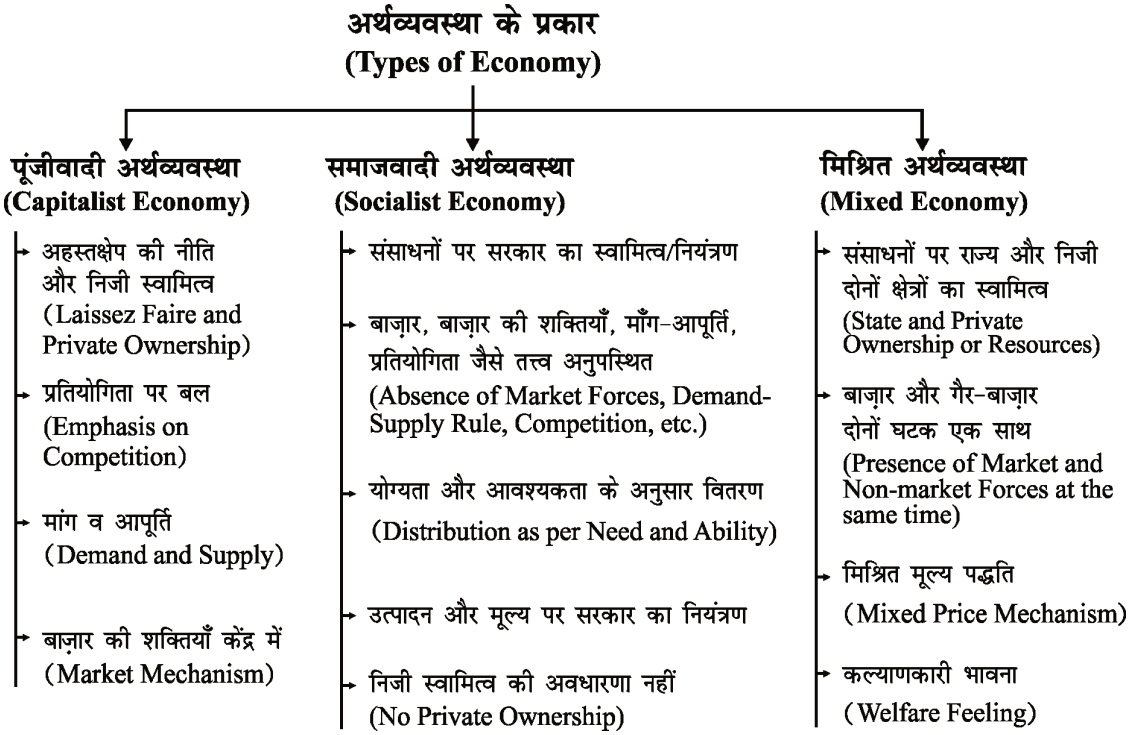

उपर्युक्त वर्गीकरण के अनुसार, वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं— अमेरिका, ब्राज़ील, मैक्सिको, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आदि; समाजवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं— चीन, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया आदि; और मिश्रित अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं- भारत, नार्वे, स्वीडन आदि।

वस्तुओं की कीमतों का निर्धारण *(Determination of prices of Goods)*

- **बाज़ार कीमत क्रियाविधि (Market Price Mechanism):** इसमें बाज़ार शक्तियों अर्थात् मांग व आपूर्ति (Demand and Supply) द्वारा कीमत निर्धारित होती है। अत: क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच मुक्त सौदेबाजी के आधार पर निर्णय लेने की पद्धति को बाज़ार कीमत क्रियाविधि (Market Price Economy) कहते हैं।

  यह क्रियाविधि पूंजीवादी दर्शन की उपज है। पूंजीवादी दर्शन एक ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था पूंजी (Capital) में निहित होती है और बाज़ार आधारित होती है। बाज़ार कीमत क्रियाविधि के अनुसार कार्यशील अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था (Free Economy) कहते हैं और सरकार की नीति को ऐसे मामले में अहस्तक्षेप की नीति (Laissez Faire) कहते हैं।
- **प्रशासित कीमत क्रियाविधि (Administered Price Mechanism):** इसमें प्रशासनिक शक्तियों (Administrative Powers) द्वारा कीमत निर्धारित होती है। अत: यदि सभी आर्थिक निर्णयों पर प्रशासन या सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो तथा क्रेताओं एवं विक्रेताओं को सौदेबाजी की कोई स्वतंत्रता न हो, तो निर्णय की इस पद्धति को प्रशासित कीमत क्रियाविधि (Administered Price Mechanism) कहते हैं।

यह क्रियाविधि समाजवादी दर्शन की उपज है। यह दर्शन ऐसी व्यवस्था का प्रतिपादन करता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है, और ऐसी क्रियाविधि के लिये व्यापक लाइसेंस नीति (Licensing Policy) अपनाई जाती है। इसका आशय हुआ कि प्रत्येक आर्थिक क्रियाकलाप के लिये सरकार की अनुमति आवश्यक होती है।

- **मिश्रित कीमत क्रियाविधि (Mixed Price Mechanism):** इस क्रियाविधि में बुनियादी निर्णय (Fundamental Decisions) प्रशासनिक शक्तियों द्वारा तथा गौण निर्णय (Secondary Decisions) बाज़ार द्वारा लिये जाते हैं। इसमें कुछ आर्थिक क्रियाकलापों (Economic Activities) पर सरकार का तो कुछ पर निजी संस्थाओं (Private Institutions) का अधिकार होता है। लाइसेंसिंग (Licensing) की प्रक्रिया चयनात्मक (Selective) होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) में बाज़ार (Market) तथा केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं (Central Planned Economy), दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं तथा इन दोनों अर्थव्यवस्थाओं की अच्छाइयों को स्वीकार किया जाता है। इसमें "क्या, कैसे और किसके लिये" उत्पादन किया जाए से संबंधित निर्णय बाज़ार की शक्तियों (Market Forces) तथा सामाजिक कल्याण (Social Welfare) दोनों के आधार पर लिये जाते हैं। जैसे–भारत में, उत्पादकों को अपने लाभ को अधिकतम करने के लिये, कपड़े या इस्पात का उत्पादन करने की स्वतंत्रता है परंतु रेलवे (Railways) पर सरकार का एकाधिकार है। ऐसा कल्याणकारी दृष्टिकोण से किया गया है ताकि आम लोगों को सस्ते परिवहन की सुविधा मुहैया कराई जा सके।

भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवाद (Capitalistic Socialism) सदृश है। समाजवाद में संपत्ति का अधिकार किसी भी तरीके से नहीं होता, लेकिन हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार (Right to Property) एक कानूनी अधिकार (Legal Right) है। भारत का रुझान समाजवाद की तरफ भी है, क्योंकि 'समावेशी विकास' (Inclusive Development) का लक्ष्य प्राप्त करना भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में पहली प्राथमिकता रही है।

भारत में 1950–1991 तक मिश्रित कीमत क्रियाविधि (Mixed Price Mechanism) लागू थी। सन् 1991 के बाद से क्रियाविधि तो मिश्रित ही रही, लेकिन उसकी रणनीति में परिवर्तन की कोशिश की गई है, परिणामस्वरूप पुरानी आर्थिक प्रणाली में बदलाव आया है।

विभिन्न देशों का उनकी अर्थव्यवस्थाओं के अनुसार वर्गीकरण *(Classification of Different Countries According to Their Economies)*

अर्थव्यवस्था के आधार पर विश्व के सभी देशों को निम्नलिखित वर्गों में रखा जा सकता है–

पहली दुनिया के देश (First World Countries): विकसित (Developed) देशों का समूह, जहाँ बाज़ार कीमत क्रियाविधि (Market Price Mechanism) प्रचलित है, पहली दुनिया के देश कहलाते हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि।

दूसरी दुनिया के देश (Second World Countries): विभिन्न देशों का वह समूह जहाँ प्रशासित कीमत क्रियाविधि (Administrative Price Mechanism) अपनाई जाती है, दूसरी दुनिया के देश कहलाते हैं, जैसे 1990 से पहले का सोवियत संघ, वर्तमान चीन आदि। आजकल ऐसी अर्थव्यवस्था संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएँ (Transitional Economies) कहलाती हैं क्योंकि ये अर्थव्यवस्थाएँ धीरे–धीरे खुले बाज़ार (Open Market) की नीति अपना रही हैं।

तीसरी दुनिया के देश (Third World Countries) : द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद आज़ाद हुए अधिकांश देशों ने विकास के लिये मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy) को अपनाया। इन्हीं को तीसरी दुनिया का देश कहा जाता है, जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल आदि। इन्हें अल्पविकसित देश (Less-developed Countries) भी कहा जाता है।

चौथी दुनिया के देश (Fourth World Countries) : विश्व में कई ऐसे देशों का एक समूह भी है जो विकास का मार्ग अपनाने के लिये द्वंद्व (Conflict) की स्थिति में हैं। इन देशों में प्रगति के पथ पर यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई है। इन्हें अल्पतम विकसित देश (Least-developed Countries) कहा जाता है, जैसे युगांडा, सूडान, रवांडा आदि।

उत्पादन के कारक *(Factors of Production)*

वे सभी तत्त्व जिनके एक साथ मिलने पर उत्पादन का कार्य पूरा होता है, उत्पादन के कारक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में, विभिन्न प्रकार के संसाधनों में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति (Productive Powers) को उत्पादन का कारक कहा जाता है। उत्पादन के कारकों को हम चार वर्गों में बाँटते हैं-

(i) श्रम (Labour) : मानव शरीर या मस्तिष्क में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति को श्रम (Labour) कहते हैं। श्रम का हस्तांतरण दो दिशाओं में होता है:

(a) ऊध्वार्धर हस्तांतरण (Vertical Transfer): निम्न कौशल से उच्च कौशल की ओर श्रम का हस्तांतरण।

(b) क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Transfer): एक उत्पादन क्षेत्र से किसी अन्य उत्पादन क्षेत्र में श्रम का हस्तांतरण।

ऊर्ध्वाधर (Vertical) तथा क्षैतिज (Horizontal) हस्तांतरण में भेद इस उदाहरण से समझा जा सकता है: यदि कोई किसान अपने खेतों में उन्नत बीजों का प्रयोग करता है और उत्पादकता (Productivity) को बढ़ाता है, तो इसे ऊर्ध्वाधर हस्तांतरण (Vertical Transfer) कहेंगे। दूसरी ओर, सरकार यदि भूमि स्वामित्व का पुनर्वितरण करती है, तो इसे क्षैतिज हस्तांतरण (Horizontal Transfer) कहेंगे। इसी प्रकार, यदि विभिन्न आर्थिक पेशे जड़ (स्थिर) न हों, मानव श्रम को आनुवंशिक पेशों से मुक्त रखा जाए और सभी को रुचि (Interest) एवं क्षमताओं (Potential) के अनुसार पेशा चुनने का अधिकार दिया जाए तो इसे श्रम की गतिशीलता अथवा हस्तांतरण कहेंगे।

(ii) भूमि (Land) : सामान्यतया भूमि का आशय पृथ्वी की सतह से ही लगाया जाता है लेकिन अर्थशास्त्र में इसे प्राकृतिक संसाधनों के संदर्भ में देखा जाता है। प्राकृतिक संसाधनों में पाई जाने वाली उत्पादन शक्ति (Productive Powers) को भूमि कहते हैं। जैसे- नदी में विद्यमान गतिज ऊर्जा नदी की उत्पादन शक्ति है, अत: इसे नदी की 'भूमि' कह सकते हैं। इसी प्रकार, बादल में विद्यमान आर्द्रता तथा मृदा की उर्वरता क्रमश: बादल और मृदा की भूमि है।

(iii) पूंजी (Capital): पूंजी का आशय ऐसे मानव निर्मित संसाधनों से है जिनका इस्तेमाल उत्पादन में किया जाता है। पूंजी के तीन रूप होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

(A) भौतिक पूंजी (Physical Capital): मानव-निर्मित (Man-made) भौतिक संसाधनों (Material Resources) की उत्पादन शक्ति (Productive Power) को भौतिक पूंजी कहते हैं। भौतिक पूंजी के उदाहरण हैं: नहर (Canal), सड़क (Road), भवन (Building), पुल (Bridge), मशीन (Machine), वाहन (Vehicle) इत्यादि।

(B) बौद्धिक पूंजी (Intellectual Capital): मानवीय विचारों (Human Thoughts) की उत्पादन शक्ति (Productive Power) को बौद्धिक पूंजी (Intellectual Capital) कहते हैं। उदाहरण के लिये साहित्यिक विचार (Literary Thoughts), वैज्ञानिक विचार (Scientific Thoughts), कलात्मक विचार (Artistic Thoughts), धार्मिक विचार (Religious Thoughts) व आविष्कार (Inventions) इत्यादि।

(C) वित्तीय पूंजी (Financial Capital): मुद्रा (Currency) एवं मुद्रा से व्युत्पन्न अन्य संसाधनों की उत्पादन शक्ति को वित्तीय पूंजी कहते हैं। वित्तीय पूंजी के उदाहरण हैं: नकद (Cash) धनराशि, आभूषण (Jewellery) संपत्ति आदि। [ध्यातव्य है कि मुद्रा का आविष्कार भारत में पाँचवीं शताब्दी ई.पू. हुआ, उससे पहले भारत में वित्तीय पूंजी बाज़ार नहीं था।]

बौद्धिक पूंजी को भी तीन वर्गों में रखा जा सकता है-

(a) कलात्मक बौद्धिक पूंजी (Artistic Intellectual Capital): कलात्मक विचारों के अन्दर की उत्पादन शक्ति (Productive Power) को कलात्मक बौद्धिक पूंजी (Artistic Intellectual Capital) कहते हैं, जैसे किताबें, लेख या चित्र आदि। कलात्मक पूंजी के स्वामित्व को **कॉपीराइट** (Copyright) कहा जाता है। इसका **संकेत :** © है।

(b) वैज्ञानिक बौद्धिक पूंजी (Scientific Intellectual Capital): वैज्ञानिक विचारों की उत्पादन शक्ति (Productive Power) को वैज्ञानिक (Scientific Intellectual Capital) बौद्धिक पूंजी कहते हैं, जैसे प्रौद्योगिकी (Technology)

या कोई वैज्ञानिक आविष्कार। वैज्ञानिक पूंजी या प्रौद्योगिकी पूंजी के स्वामित्व को पेटेंट (Patent) कहा जाता है। इसका **संकेत :** ® है।

(c) **व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी (Business Intellectual Capital):** किसी व्यवसाय को चलाने के लिये जिन विचारों का प्रयोग होता है, उन विचारों की उत्पादन शक्ति (Productive Power) को व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी (Business Intellectual Capital) कहते हैं, जैसे टाटा द्वारा नैनो कार निर्माण का विचार आदि। व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को **ट्रेड मार्क** (Trade Mark) कहा जाता है। इसका **संकेत :** ™ है।

(iv) **उद्यमशीलता (Enterpreneurship) :** किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह में पाई जाने वाली एक संश्लिष्ट उत्पादन शक्ति (Synthesised Productive Power) को उद्यमशीलता (Enterpreneurship) कहते हैं। इसके तीन अवयव होते हैं, जो निम्नलिखित हैं-

उद्यमशीलता (Enterpreneurship)

नवाचार भूख (Innovation Appetite)	**प्रबंधन भूख (Management Appetite)**	**जोखिम भूख (Risk Appetite)**
किसी कार्य विशेष में नये विचारों या संसाधनों को अपनाने की अन्तर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को 'नवाचार भूख'कहते हैं।	किसी कार्यक्रम विशेष में अन्य संसाधन धारकों जैसे भूपतियों, श्रमिकों एवं पूँजीपतियों के प्रयासों को संगठित करने की अन्तर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को 'प्रबंधन भूख' कहते हैं।	नवाचार एवं प्रबंधन में पाए जाने वाले जोखिम को नपे-तुले रूप से अपनाने की अन्तर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को 'जोखिम भूख' कहते हैं।

स्पष्ट है कि किसी कार्य विशेष को करने की अन्तर्निहित गतिशील प्रवृत्ति को भूख (Appetite) कहते हैं। किसी भी उद्यम के लिये उपर्युक्त तीनों प्रवृत्तियों का तीव्र होना आवश्यक है। उद्यम आर्थिक के साथ-साथ सामाजिक, राजनीतिक आदि भी हो सकता है क्योंकि हर उद्यम (Enterprise) में नवाचार (Innovative), प्रबंधन (Management) तथा जोखिम जैसे अवयव विद्यमान होते हैं।

उत्पादन के विभिन्न क्षेत्र *(Different Sectors of Production)*

उत्पादन की प्रकृति के आधार पर उत्पादन क्रियाओं को तीन क्षेत्रों में बाँटा जाता है–

- **प्राथमिक क्षेत्र (Primary Sector) :** नैसर्गिक संसाधनों (Natural Resources) के प्रत्यक्ष दोहन (Direct Utilization) द्वारा जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए उन्हें प्राथमिक वस्तुएँ (Primary Goods) कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना (Institutional Structure) को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं।
- **द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) :** प्राथमिक वस्तुओं में एक या कई बार मूल्यवर्धन द्वारा द्वारा जिन नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाए, उन्हें द्वितीयक वस्तुएँ (Secondary Goods) कहते हैं तथा ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को द्वितीयक क्षेत्र (Secondary Sector) कहते हैं।
- **तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) :** अदृश्य सेवाओं (Invisible Services) को तृतीय वस्तुएँ (Tertiary Goods) कहते हैं तथा सेवाओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को तृतीयक क्षेत्र (Tertiary Sector) कहते हैं।

आय का चक्रीय प्रवाह *(Cyclic Flow of Income)*

किसी भी अर्थव्यवस्था में कारक सेवाओं (Factor Services) तथा अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के परस्पर निर्भर प्रवाहों (Flow of Final Goods and Services) को आय का चक्रीय प्रवाह (Cyclic Flow of Income) कहा जाता है। चूँकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए एक चक्र (Cycle) के रूप में कार्य करते हैं इसलिये इसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इसे निम्न आरेख से समझा जा सकता है-

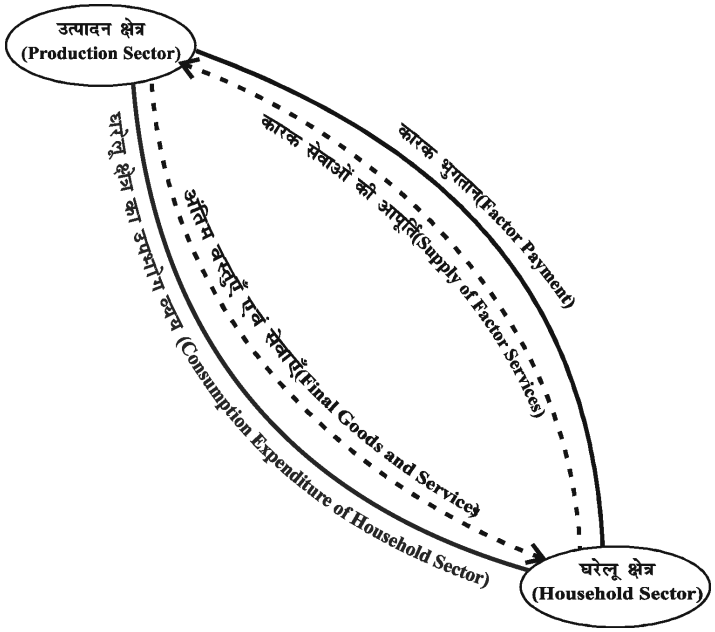

उत्पादन क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र के संबंधों को जानने के लिये 'कारक आय' की अवधारणा स्पष्ट करना आवश्यक है। कारक आय से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित उस आय से है जो उसे कारक सेवा के बदले में प्राप्त होती है। यह उसके श्रम के बदले में मज़दूरी, उसकी भूमि के लिये लगान, पूंजी के लिये ब्याज तथा उद्यमिता (Entrepreneurship) के लिये लाभ के रूप में हो सकती है। इसमें ऐसी कोई भी आय शामिल नहीं होती जो अर्जित नहीं की गई है अथवा जिसके बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं की गई है। उदाहरण के लिये, वरिष्ठ नागरिकों को प्राप्त होने वाली वृद्धावस्था पेंशन अर्जित आय (Earned Income) नहीं है। ऐसी प्राप्तियों या भुगतानों को हस्तांतरण प्राप्तियाँ या हस्तांतरण भुगतान (Transfer Receipts or Transfer Payments) कहा जाता है। इसको राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता है।

आय के चक्रीय प्रवाह का वर्गीकरण *(Classification of Cyclic Flow of Income)*

आय के चक्रीय प्रवाह को दो प्रकार से वर्गीकृत (Classify) किया जा सकता है। पहला, स्वरूपगत लक्षण के आधार पर तथा दूसरा, गुणात्मक आधार पर।

- स्वरूपगत लक्षण के आधार पर वर्गीकरण (Formal Classification)
  - नाममात्र आय का चक्रीय प्रवाह (Cyclic Flow of Nominal Income)
  - वास्तविक आय का चक्रीय प्रवाह (Cyclic Flow of Real Income)
- गुणात्मक वर्गीकरण (Functional/Qualitative Classification)
  - आय का कुचक्र (Vicious Circular Flow of Income)
  - आय का सुचक्र (Virtuous Circular Flow of Income)

आय के चक्रीय प्रवाह को बाधित करने वाली चुनौतियाँ *(Factors that Cause Disturbance to the Cyclic Flow of Income)*

किसी अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह को बाधित (Disturb) करने वाली चुनौतियों को दो वर्गों में रखा जा सकता है— बाह्यजन्य चुनौतियाँ और अंतर्जात चुनौतियाँ।

बाह्यजन्य चुनौतियाँ (Exogenous Challenges)

ये चुनौतियाँ आर्थिक प्रणाली के बाहर से उत्पन्न होती हैं।

उदाहरणार्थ, (i) बाह्य आक्रमण या आक्रमण का खतरा

(जैसे 18-19वीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कंपनी का भारत पर शासन)

(ii) आंतरिक अस्थिरता या अराजकता

(जैसे माओवाद, नक्सलवाद, दिन-प्रतिदिन के अपराध)

(iii) न्याय का अभाव/विलंबित न्याय

(जैसे भारत के न्यायालयों में वर्तमान में लगभग 2.2 करोड़ मामले विलंबित हैं)

अंतर्जात चुनौती (Endogenous Challenges)

ये चुनौतियाँ आर्थिक प्रणाली के अन्दर से उत्पन्न होती हैं।

उदाहरणार्थ, मूल्य विचलन (Price Instability)

मूल्य विचलन दो दिशाओं में होता है:

⇒ ऊर्ध्वमुखी (Upward) विचलन को मुद्रास्फीति (Inflation) या महँगाई कहते हैं।

⇒ अधोमुखी (Downward) विचलन को अवस्फीति (Deflation) कहते हैं।

मुद्रास्फीति *(Inflation)*

किसी अर्थव्यवस्था में किसी कालावधि विशेष में वस्तुओं व सेवाओं के सामान्य मूल्य-स्तर में वृद्धि हो जाने की स्थिति मुद्रास्फीति (Inflation) कहलाती है। यह मांग प्रेरित भी हो सकती है और लागत जन्य भी।

1. **मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation):** यदि वस्तुओं की आपूर्ति (Supply) के सापेक्ष वस्तुओं की मांग (Demand) में आधिक्य उत्पन्न हो तो क्रेता (Buyers) या उपभोक्ता (Consumers) आपस में स्पर्धा करते हुए ऊँची कीमत की बोली लगाते हैं, जिससे कीमत बढ़ जाती है। इसलिये इसे मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति (Demand-Pull Inflation) कहते हैं।

   मांग-प्रेरित मुद्रास्फीति के निम्नलिखित कारण हैं—
   - उत्पादन के सापेक्ष जनसंख्या में तीव्रतर वृद्धि।
   - उत्पादन के सापेक्ष मुद्रा आपूर्ति (Supply of Money) में अधिक वृद्धि।
   - सरकार की आय प्राप्ति के सापेक्ष उच्चतर व्यय (Higher Expenditure)।
   - विदेशों से प्राप्त अतिरिक्त मुद्रा राशि।
   - आय वितरण में असमानता।
   - अवैध आय (Black Income) से भी महँगाई आती है।

   एक अनुमान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कानूनी अर्थव्यवस्था दो-तिहाई है और गैर-कानूनी अर्थव्यवस्था एक-तिहाई है। अवैध आय से संचालित अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था (Parallel Economy) कहा जाता है।

2. **लागतजन्य मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation):** कारक सेवाओं (Factor Services) की एक निश्चित मात्रा के बदले में किये गए कारक भुगतान (Factor Payment) की मात्रा में यदि वृद्धि हो जाए अर्थात् उत्पादन लागत (Cost of Production) बढ़ जाए तो उत्पाद की कीमत (Price of Product) बढ़ जाती है, जिसे लागतजन्य मुद्रास्फीति (Cost-Push Inflation) कहते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था में श्रम लागत (Labour Cost) में वृद्धि होने पर महँगाई बढ़ जाती है, इसके अलावा कुछ अन्य कारक भी इसके लिये ज़िम्मेदार हो सकते हैं, जैसे –
   - मज़दूरी लागत (Labour Cost)
   - कर लागत (Tax of Cost)
   - उद्योगपतियों को ज़्यादा आय
   - परोक्ष करों (Indirect Taxes) की लागत

अवस्फीति *(Deflation)*

किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं एवं सेवाओं के सामान्य मूल्य-स्तर में गिरावट की स्थिति अवस्फीति (Deflation) कहलाती है। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की दर शून्य प्रतिशत से नीचे चली जाती है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है।

अवस्फीति के कारण *(Causes of Deflation)*

- यदि मांग (Demand) के सापेक्ष आपूर्ति (Supply) अधिक हो या आपूर्ति के सापेक्ष मांग कम हो तो अवस्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है।
- यदि कानूनी उपाय (Legal Methods) द्वारा सरकार कीमतों को कम करे तो अवस्फीति उत्पन्न होती है।
- यदि उत्पादकों (Producers) के बीच स्पर्धा (Competition) अधिक हो तो कीमतें गिर जाती हैं।
- यदि सरकार कर अवकाश (Tax Holidays) की घोषणा कर दे तो भी अवस्फीति (Deflation) की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।

बचत की अवधारणा
(Concept of Saving)

वर्तमान आय का वह अंश जिसे भविष्य (Future) में उपभोग के लिये बचा लिया जाए अर्थात् आज उपभोग (Consumption) पर व्यय न किया जाए, उसे बचत (Saving) कहते हैं।

$$\boxed{I(\text{आय}) = C(\text{उपभोग}) + S(\text{बचत})}$$

वित्त क्षेत्र की दृष्टि से बचत के निम्नलिखित प्रकार हैं–

बचत (Savings)

घरेलू बचत
(Household Savings–S_h)
देश के घरेलू क्षेत्र द्वारा की गई कुल बचत को 'घरेलू बचत' कहते हैं।

सरकारी बचत
(Savings of Government–S_g)
देश की सरकार द्वारा की गई कुल बचत को 'सरकारी बचत' कहते हैं।

निगम बचत
(Corporate Savings–S_c)
देश के संपूर्ण निगम क्षेत्र (India Incorporate) द्वारा की गई कुल बचत को निगम बचत कहते हैं।

- सार्वजनिक निगम बचत (Public Sector Savings)
- निजी निगम बचत (Private Sector Savings)

$$\boxed{S_h > S_c > S_g}$$

किसी भी देश में घरेलू बचत का मान सर्वाधिक होता है। उसके बाद क्रमशः निगम और सरकारी बचत आते हैं। साधारणतः सरकारी बचत (S_g) का मान ऋणात्मक होता है और इस ऋणात्मक राशि को राजकोषीय घाटा (Fiscal Deficit) कहते हैं। चूँकि पैसे को उदासीन (Neutral) रखने का कोई लाभ नहीं होता, इसलिये उसका उत्पादन कार्य में निवेश किया जाना चाहिये। ऐसे निवेश को सकल घरेलू निवेश (Gross Domestic Investment) कहते हैं।

$$\boxed{\text{सकल घरेलू बचत (GDS)} = S_h + S_c + S_g}$$

बचत की विद्यमानता (Presence of Saving) के आधार पर आय दो प्रकार की होती है:

आय (Income)

निर्वाह आय
(Subsistence Income)

यदि आय की मात्रा इतनी कम हो कि किसी प्रकार से वर्तमान ज़रूरतों की पूर्ति हो जाए तो ऐसी आय को 'निर्वाह आय' कहते हैं।

अधिशेष आय
(Surplus Income)

यदि आय की मात्रा इतनी अधिक हो कि वर्तमान जरूरतों की पूर्ति के बाद आय का एक उल्लेखनीय अंश भविष्य की ज़रूरतों के लिए शेष रह जाए तो ऐसी आय को 'अधिशेष आय' कहते हैं।

जिस देश/राज्य/जिले के ज़्यादातर उत्पादकों की आय निर्वाह स्तर (Subsistence Level) की हो वहाँ की अर्थव्यवस्था **निर्वाह अर्थव्यवस्था** (Subsistence Economy) कहलाती है। दूसरी ओर, जिस देश/राज्य/जिले के ज़्यादातर उत्पादकों की आय अधिशेष स्तर (Surplus) की हो वहाँ की अर्थव्यवस्था **अधिशेष अर्थव्यवस्था** (Surplus Economy) कहलाती है।

निवेश की अवधारणा *(Concept of Investment)*

ऐसा व्यय जिससे उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलती है, निवेश कहलाता है। निवेश का उत्पादन पर दो प्रकार से प्रभाव पड़ता है, जो निम्नलिखित है–

अल्पकालिक प्रभाव
(Short-Term Effects)

यदि निवेश द्वारा वर्तमान उत्पादन क्षमता के दोहन (Utilization) में सुधार किया जाए तो उत्पादन में अल्पकालिक वृद्धि होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसान खेत में अच्छे बीज और उर्वरक का इस्तेमाल करता है तो उस वर्ष फसल अच्छी होती है।

दीर्घकालिक प्रभाव/सतत् प्रभाव
(Long-Term Effects)

ऐसा निवेश जिससे उत्पादन क्षमता में विस्तार हो तो उत्पादन की सतत् वृद्धि का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, किसान ट्रैक्टर खरीदकर कई वर्षों तक उसकी सेवा लेकर उत्पादन बढ़ा सकता है।

सतत् विकास हेतु दो उपकरण
(Two Tools for Sustainable Development)

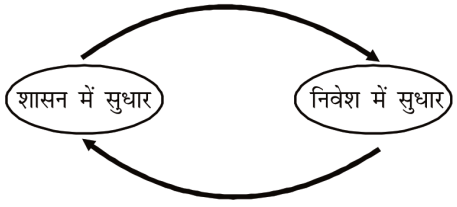

उपर्युक्त दोनों उपकरणों में संबंध रेखीय (Linear) न होकर चक्रीय (Circular) है अर्थात् शासन में सुधार के साथ ही निवेश में वृद्धि (Growth in Investment) होती है, जिससे अर्थव्यवस्था में सुधार आता है तथा अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ शासन में सुधार आता है।

निर्यात *(Export)*

निर्यात का अर्थ है– वस्तुओं व सेवाओं को किसी अन्य देश में बेचना या भेजना।

निर्यात बढ़ाने के लाभ (Advantages of Increasing Export): निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता

है जिससे देश के व्यापारियों का उत्साह बढ़ता है और उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। सेज (Special Economic Zone–SEZ) स्थापित कर निर्यात बढ़ाएंगे तो उत्पादकों (Producers) को निर्यात बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। इसके परिणामस्वरूप निवेश बढ़ेगा तथा निवेश बढ़ने से क्रमिक रूप से (Gradually) रोज़गारों की संख्या बढ़ेगी और रोज़गारों की संख्या बढ़ने के परिणामस्वरूप समाज की आय बढ़ेगी। समाज की आय बढ़ने से समाज का उपभोग (Consumption) स्तर बेहतर होगा और लोग गरिमामय जीवन के लिये अग्रसर होंगे। इसके साथ ही, लोगों को बचत (Savings) बढ़ाने की प्रेरणा मिलेगी। इस प्रकार वे बचत का निवेश करके ब्याज (Interest) कमा सकेंगे। इस प्रकार पुनः आय बढ़ेगी और संपूर्ण प्रक्रिया की परिणति (Result) आय के सुचक्र अर्थात् वर्तुलाकार ऊर्ध्वमुखी दबाव (Spiral-up Pressure) में होगी। अतः निर्यात बढ़ाने का लाभ (Profit of Maximizing Export) व्यापारियों को पहले प्रत्यक्ष रूप से और फिर आम जनता को समय के साथ क्रमिक रूप से मिलेगा।

निर्यात की हानियाँ *(Disadvantages of Exporting)*

- यदि देश में वस्तुओं की उपलब्धता कम होगी तो उस वस्तु के निर्यात को प्रोत्साहित (Encourage) करने से देश में वस्तु की आपूर्ति कम होगी और इस प्रकार महँगाई बढ़ेगी।
- निर्यात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा (Foreign Currency) का भंडार बढ़ेगा, जिसकी परिणति घरेलू मुद्रा (Domestic Currency) की मात्रा बढ़ने में होगी और इस प्रकार महँगाई बढ़ेगी। महँगाई बढ़ने से जनता के उपभोग स्तर में अनियमितता आएगी।
- निर्यात बढ़ाने से निर्यात क्षेत्र की आय बढ़ेगी और वहाँ कार्यरत मज़दूर, मज़दूरी बढ़ाने का दबाव बनाएंगे, जिससे आय विषमता (Income Inequality) बढ़ेगी।
- गैर-नवीकरणीय (Non-renewable) भंडार का निर्यात बढ़ाएंगे तो सतत् विकास की प्रक्रिया में मुश्किलें बढ़ेंगी। कई प्रकार के कच्चे माल (लौह-अयस्क आदि), जिनकी उपलब्धता हमारे देश में पहले से ही कम है, का निर्यात बढ़ाने पर घरेलू उद्योगों (Domestic Industries) पर प्रतिकूल प्रभाव (Negative Impact) पड़ेगा।
- जिस देश को निर्यात किया जाएगा वहाँ के उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उस देश के व्यापारियों की आय कम होगी और वहाँ रोज़गार में कमी आएगी। इसके परिणामस्वरूप, उस देश के साथ संबंधों में तनाव (Tension) आ सकता है।
- निर्यात बढ़ने से अन्य देशों पर निर्भरता (Dependency) बढ़ जाती है और वहाँ मंदी (Slow-down) आने से घरेलू अर्थव्यवस्था में भी मंदी आ सकती है।

निर्यात नियंत्रण के उपाय *(Measures to Control Export)*

उपर्युक्त हानियों को देखते हुए, किसी भी अर्थव्यवस्था में निर्यात पर नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपाय किये जा सकते हैं:

- निर्यात सीमित होना चाहिये ताकि घरेलू अर्थव्यवस्था (Domestic Economy) पर दुष्प्रभाव न पड़े तथा साथ ही गैर-नवीकरणीय संसाधनों (Non-renewable Resources) के निर्यात के स्थान पर सेवा निर्यात (Service Export) और फसलों के निर्यात को वरीयता देनी चाहिये।
- चूँकि शहरों की आय पहले से ही ज़्यादा है, इसलिये निर्यात को एक ऐसे उपकरण (Instrument) की तरह इस्तेमाल करना चाहिये जिससे शहर और गाँव के मध्य विषमता में कमी आये।

आयात *(Import)*

आयात का अर्थ है— वस्तुओं व सेवाओं को किसी अन्य देश से खरीदना अथवा मँगवाना। इस व्यवस्था में विदेशी उत्पादकों (Foreign Producers) द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं (Domestic Consumers) को वस्तुएँ एवं सेवाएँ बेची जाती हैं।

आयात बढ़ाने के लाभ *(Advantages of Increasing Import)*

आयात बढ़ाने से किसी अर्थव्यवस्था को क्या लाभ पहुँचता है, निम्नांकित बिंदुओं से स्पष्ट होता है:

- जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता, जैसे सोना, चाँदी, कच्चा तेल आदि, उनका आयात करने से देश का उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ने से देश का उपभोग स्तर उन्नत होगा। उपभोग स्तर उन्नत होने से जनता गरिमामय जीवन (Dignified Life) की ओर अग्रसर होगी तथा पुन: आय के साथ अपना बचत बढ़ाएगी और बचत का निवेश करेगी। निवेश बढ़ने से क्रमिक रूप से रोज़गारों की संख्या बढ़ेगी और रोज़गारों की संख्या बढ़ने के साथ-साथ समाज की आय भी बढ़ेगी।
- जिन प्रौद्योगिकियों (Technologies) का उत्पादन हमारे देश में नहीं होता उनका आयात करने पर हमारी तकनीकी उन्नति (Technical Development) होगी। उदाहरण के लिये मशीनों का आयात करके विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone–SEZ) स्थापित करने से देश की उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा और वस्तुओं का निर्यात होने से पुन: रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे।
- आयात करने से घरेलू उत्पादकों में प्रतिस्पर्धा (Competition) बढ़ेगी। इससे वस्तुओं की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, साथ ही महँगाई में भी कमी आएगी।
- आयात बढ़ने से सरकार को कर की प्राप्ति होगी और सरकार पूंजी प्राप्त कर बेहतर ढंग से 'कल्याणकारी कार्य' कर सकेगी।
- तत्काल उत्पादन क्षमता में सुधार किये जाने से अनुसंधान और विकास (Research and Development) की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा।
- वैध रूप से आयात की अनुमति मिलने से अवैध आयात (तस्करी/Smuggling) की प्रवृत्ति पर स्वत: रोक लगेगी।

आयात की हानियाँ *(Disadvantages of Importing)*

किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं व सेवाओं का स्वयं उत्पादन करने की बजाय उन्हें किसी अन्य देश से खरीदने अथवा मंगवाने के प्रतिकूल परिणामों अथवा हानियों को बिंदुवार इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है:

- आयात उदारीकरण (Import Liberalization) से अंतर्राष्ट्रीय निर्भरता बढ़ेगी जो कि भारत पर बाह्य संप्रभुता के लिये दबाव उत्पन्न करेगी।
- यदि ऐसी वस्तुओं का आयात किया जाएगा जिनकी पर्याप्त उपलब्धता पहले से ही देश में है तो घरेलू उत्पादकों (Domestic Producers) को नुकसान होगा। इससे कई उत्पादक इकाइयाँ बंद हो सकती हैं और रोज़गार में कमी आ सकती है।

> **आयात उदारीकरण *(Import Liberalization):*** *किसी अर्थव्यवस्था द्वारा आयातित वस्तुओं व सेवाओं पर प्रशुल्क, कोटा, अधिनियमों, कर व अन्य प्रतिबंधों में छूट दिये जाने को आयात उदारीकरण (Import Liberalization) कहा जाता है।*

- केवल आयात करने से एवं घरेलू उत्पादन की उपेक्षा करने से घरेलू उत्पादन बंद होगा और देश की अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा।
- आयात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign Currency Reserve) कम होगा।
- यदि विदेशी मुद्रा का भंडार कम होगा तो विदेशी सरकारों पर अनुदान हेतु निर्भरता (Dependency) बढ़ेगी और इससे देश को कूटनीतिक (Diplomatic) नुकसान हो सकता है।
- अत्यधिक आयात से लोगों में विदेशी संस्कृति के प्रति अंध-श्रद्धाभाव (Blind Faith) बढ़ सकता है।

आयात नियंत्रण के उपाय *(Measures to Control Import)*

आयात उदारीकरण से उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को नज़र में रखते हुए, अवांछित आयात (Unwanted Import) पर नियंत्रण रखने के साथ ही आयात उदारीकरण की नीति लागू करनी चाहिये। इस प्रकार, अंधी-दौड़ में शामिल न होकर विवेकसंगत निर्णय (Prudential Decision) लिया जाना चाहिये।

बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश *(Outward Foreign Investment)*

देशी बचत राशि का विदेशों में निवेश बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश कहलाता है।

बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश के लाभ *(Advantages of Outward Foreign Investment)*

- इससे विदेशों से लाभ और ब्याज कमाने में मदद मिलती है। साथ ही, अन्य देशों में अपने प्रशिक्षित कामगारों (Trained Workers) को रोज़गार दिलाने में मदद मिलती है।
- इससे देश को कूटनीतिक फायदा होता है क्योंकि साझेदार देश में उत्पादन और रोज़गार बढ़ाने में मदद मिलती है।
- मित्र देशों में खाद्य, पूंजी आदि द्वारा सहायता पहुँचाने से बाह्य संप्रभुता (Sovereignty) भी सशक्त होती है और इस प्रकार समर्थक देशों की संख्या बढ़ती है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में निवेशक देशों की साझेदारी को वास्तविक धरातल (Real Ground) प्राप्त होता है।
- इससे सांस्कृतिक लाभ (Cultural Benefits) भी मिलते हैं क्योंकि इससे निवेशक देशों की संस्कृति का विश्व भर में प्रचार होता है और दूसरे देशों में छवि बेहतर होती है।

बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश की हानियाँ *(Disadvantages of Outward Foreign Investment)*

किसी अर्थव्यवस्था में अधिक बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश (Outward Foreign Investment) से देशी निवेश के लिये निधि (Funds) की उपलब्धता कम हो सकती है। अत: जब घरेलू बचत राशि (Domestic Saving Amount) पर्याप्त हो तभी ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिये अन्यथा देश में वस्तुओं की खपत गिरेगी, जिससे घरेलू उत्पादकों को नुकसान होगा। अत: मितव्ययिता बढ़ाकर ज्यादा बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश किया जाना चाहिये। इस प्रकार के निवेश की अन्य हानियाँ हैं:

- स्पर्धात्मक कूटनीतिक युग (Competitive Diplomatic Era) में कुछ देशों को मदद करने पर अन्य देश बुरा मान सकते हैं। अत: देश को कूटनीतिक नुकसान (Diplomatic Loss) हो सकता है।
- जिस देश में निवेश को बढ़ावा मिलेगा वहाँ के नागरिक-समाज (Civil Society) में हमारे प्रति गलतफहमी पैदा हो सकती है और अन्य देश इसका दुष्प्रचार कर सकते हैं।
- यदि हमारी संस्कृति (Culture) का अन्य देश में विस्तार होता है तो वहाँ उस देश की संस्कृति पर दबाव पड़ता है।
- सहायता राशि का भी अन्य देश द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है।
- दूसरे देश के स्थानीय कामगारों (Local Workers) में हमारे कामगारों के प्रति अवांछित प्रतिस्पर्धा (Unwanted Competition) की भावना का विकास हो सकता है।

बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश पर नियंत्रण के उपाय *(Measures to Control Outward Foreign Investment)*

बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश से पहले मित्र देश के नागरिक-समाज को विश्वास में लेना चाहिये। साथ ही, उसे वहाँ के मज़दूरों को पारदर्शी (Transparent) तरीके से शामिल करना चाहिये। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिये कि विरोधी देश किसी भी प्रकार की अफवाहें (Rumours) न फैलाएँ।

अन्तर्मुखी विदेशी निवेश *(Inward Foreign Investment)*

अन्य देशों से देश के अंदर आने वाले निवेश को अन्तर्मुखी विदेशी निवेश (Inward Foreign Investment) कहते हैं।

अंतर्मुखी विदेशी निवेश के लाभ *(Advantages of Inward Foreign Investment)*

- इससे घरेलू निवेश को बचत राशि से ऊँचा उठाने में मदद मिलती है।

- बेरोज़गारी का त्वरित गति से ह्रास (Rapid Decline) होता है और उत्पादन एवं आय बढ़ाने में मदद मिलती है। लोगों की आय बढ़ने से सरकार की कर-प्राप्ति में वृद्धि होती है।
- विदेशी निवेश से आधारभूत संरचना (Basic Infrastructure) का तेजी से विकास होता है और घरेलू बुनियादी ढाँचा सुदृढ़ होता है। इस प्रकार संपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप (Economic Activities) में तेजी आती है।
- पूंजी भंडार क्षेत्र (Capital Reserve Sector) में सक्रियता बढ़ती है। विदेशी धन का निवेश यदि ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है तो गाँवों की उन्नति के साथ लोगों का शहर की ओर पलायन (Migration) कम होता है और इस प्रकार 'भारत' और 'इंडिया' का द्वैत कम करने में मदद मिलती है।
- परंपरागत (Traditional) लघु और कुटीर उद्योगों में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें पुनर्जीवित करने में मदद मिलती है।
- निर्यात को प्रोत्साहित करने वाले जितने कार्यक्रम हैं यदि उनमें विदेशी निवेश आता है तो निर्यात संवर्धन (Export Expansion) में मदद मिलती है।
- जिन देशों से वित्त (Finance) आयात होता है उनसे कूटनीतिक संबंधों (Diplomatic Relations) में सुधार होता है।

अन्तर्मुखी विदेशी निवेश की हानियाँ
(Disadvantages of Inward Foreign Investment)

- किसी भी अर्थव्यवस्था में अधिक अन्तर्मुखी विदेशी निवेश से विदेशों पर निर्भरता बढ़ेगी और देश की स्वतंत्र विदेश नीति (Independent Foreign Policy) में बाधा आएगी।
- यदि हम विलासितापूर्ण वस्तुओं (Luxury Goods) के उत्पादन में विदेशी निवेश को बढ़ावा देते हैं तो देश की उपभोक्तावादी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलता है।
- देश पर विदेशी ऋण का भार बढ़ सकता है और ऋण पर ब्याज की देयता आगे चलकर असह्य (Intolerable) हो सकती है।
- यदि निवेश पिछड़े अंचलों की बजाय विकसित अंचलों में किया जाए तो आंचलिक विषमता (Inequality) बढ़ सकती है।
- सतर्क नीति की बजाय अविवेकपूर्ण उदारीकरण (Irrational Liberalization) की नीति अपनाने से संसाधनों के दोहन के स्थान पर शोषण (Exploitation) की प्रवृत्ति (पर्यावरणीय प्रदूषण का बढ़ना) बढ़ सकती है।
- इससे सामाजिक-राजनीतिक विचलन (Socio-Political Deviation) भी आ सकता है। उदाहरणार्थ, यदि विदेशी मुद्रा का निवेश ऐसे क्षेत्रों में किया जाए जो मूलतः रोज़गार/श्रम गहन हो तो बेरोज़गारी बढ़ने की आशंका हो सकती है।
- विदेशी निवेशों का अविवेकपूर्ण उदारीकरण करने से उत्पादकों पर असह्य दबाव पड़ सकता है, जिससे कई बंद हो सकते हैं, और देश में नव-उपनिवेशवाद (Neo-colonialism) का खतरा उत्पन्न हो सकता है।

अन्तर्मुखी विदेशी निवेश पर नियंत्रण के उपाय
(Measures to Control Inward Foreign Investment)

किसी भी देश को विदेशी निवेश से पहले उसकी चुनौतियों से निपटने के लिये एक विनियामक संस्था (Regulating Institution) स्थापित करनी चाहिये जो कि स्वयं चयनात्मक रूप से विदेशी मुद्रा का अनुमोदन करे तथा साथ ही, वह विवाद निपटाने के लिये अलग से एक अधिकरण (Tribunal) बना दे। इस प्रकार के निवेश पर नियंत्रण रखने के लिये सर्वप्रथम देश के कमज़ोर उत्पादन क्षेत्र का वित्तीय एवं प्रौद्योगिकीय सशक्तीकरण किया जाए और कौशल उन्नयन भी तथा साथ ही, अनावश्यक भय की आशंका को रोकने के लिये देश में जागरूकता का विकास (Development of Awakening) भी होना चाहिये।

अभ्यास हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   (i) उत्पादक उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिये स्वतंत्र हैं जिनकी मांग अधिक है।
   (ii) उपभोक्ता अपने चयन एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिये स्वतंत्र होते हैं।

   उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ हैं?
   (a) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था
   (b) समाजवादी अर्थव्यवस्था
   (c) मिश्रित अर्थव्यवस्था
   (d) अर्द्धविकसित अर्थव्यवस्था

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   (i) पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण के तत्त्व समाविष्ट होते हैं।
   (ii) श्रम विभाजन व विनिमय समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएँ हैं।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   (i) मिश्रित कीमत क्रियाविधि में बुनियादी निर्णय प्रशासनिक शक्तियों द्वारा तथा गौण निर्णय बाज़ार द्वारा लिये जाते हैं।
   (ii) भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी समाजवाद (Capitalistic Socialism) के नजदीक है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य नहीं है/हैं?
   (a) केवल (i) (b) केवल (ii)
   (c) (i) और (ii) दोनों
   (d) न तो (i) और न ही (ii)

4. उत्पादन के निम्नलिखित कारकों में से किसमें 'जोखिम' की अवधारणा निहित है?
   (a) भूमि (b) पूंजी
   (c) श्रम (d) उद्यमशीलता

5. निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 'संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाएँ' (Transitional economics) कहलाती हैं?
   (a) पहली दुनिया के देश
   (b) दूसरी दुनिया के देश
   (c) तीसरी दुनिया के देश
   (d) चौथी दुनिया के देश

6. आभूषण (Jewellery) उदाहरण है-
   (a) भौतिक पूंजी का
   (b) वित्तीय पूंजी का
   (c) बौद्धिक पूंजी का
   (d) कलात्मक बौद्धिक पूंजी का

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
   (i) वैज्ञानिक पूंजी या प्रौद्योगिकी पूंजी के स्वामित्व को पेटेंट (Patent) कहा जाता है।
   (ii) व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को कॉपीराइट (Copyright) कहा जाता है।
   (iii) कलात्मक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क (Trade Mark) कहा जाता है।

   उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से असत्य है/हैं?
   (a) केवल (i) और (ii)
   (b) केवल (ii) और (iii)
   (c) केवल (i) और (iii)
   (d) (i), (ii) और (iii)

8. नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को कहते हैं-
   (a) प्राथमिक क्षेत्र (b) द्वितीयक क्षेत्र
   (c) तृतीयक क्षेत्र (d) चतुर्थ क्षेत्र

9. निम्नलिखित में से द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है-
   (a) विनिर्माण
   (b) निर्माण
   (c) खनन एवं उत्खनन
   (d) जल विद्युत एवं गैस आपूर्ति

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) हस्तांतरण प्राप्तियाँ या हस्तांतरण भुगतान को राष्ट्रीय आय के अनुमान में शामिल नहीं किया जाता।
    (ii) विदेशों से प्राप्त अतिरिक्त मुद्रा राशि मांग प्रेरित कीमत वृद्धि का कारण है।

    उपरोक्त कथनों में सत्य है/हैं-
    (a) केवल (i)
    (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों
    (d) न तो (i) और न ही (ii)

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) साथ-साथ चलने वाली कानूनी व गैर-कानूनी अर्थव्यवस्था को समानांतर अर्थव्यवस्था कहते हैं।
    (ii) यदि आपूर्ति के सापेक्ष मांग कम हो तो मुद्रा स्फीति उत्पन्न होती है।

    उपरोक्त कथनों में सत्य है/हैं-
    (a) केवल (i)
    (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों
    (d) न तो (i) और न ही (ii)

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) यदि कानूनी उपाय द्वारा सरकार कीमतों को कम करे तो अवस्फीति उत्पन्न होती है।
    (ii) यदि सरकार टैक्स अवकाश की घोषणा करे तो अवस्फीति उत्पन्न हो सकती है।
    (iii) यदि उपभोक्ताओं के बीच स्पर्द्धा हो तो कीमतें कम हो जाती हैं।

    उपरोक्त कथनों में असत्य नहीं है/हैं-
    (a) केवल (i) और (ii)
    (b) केवल (ii) और (iii)
    (c) केवल (i) और (iii)
    (d) (i), (ii) और (iii)

13. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) उत्पाद शुल्क व विक्रय कर परोक्ष कर के उदाहरण नहीं हैं।
    (ii) देश में घरेलू बचत का मान सर्वाधिक है, उसके बाद क्रमशः निगम और सरकारी बचत आते हैं।

    उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
    (a) केवल (i)
    (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों
    (d) न तो (i) और न ही (ii)

14. मांग प्रेरित कीमत वृद्धि का कारण है–
    (i) विदेशों से प्राप्त अतिरिक्त मुद्राराशि।
    (ii) परोक्ष करों की लागत।
    (iii) उद्योगपतियों को ज़्यादा आय।
    (iv) आय-वितरण में असमानता।

    उपरोक्त कथनों में से कौन-सा/से सत्य नहीं है/हैं?
    (a) केवल (i) और (ii)
    (b) केवल (ii) और (iii)
    (c) केवल (i) और (iv)
    (d) केवल (ii) और (iv)

15. समाजवादी अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है–
    (a) योग्यता और आवश्यकता के अनुसार वितरण।
    (b) श्रम-विभाजन और विनिमय।
    (c) सरकार अंतिम निर्णायक के रूप में।
    (d) निजी स्वामित्व की धारणा नहीं।

16. निम्न कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) 'द वेल्थ ऑफ नेशन्स' पुस्तक के लेखक पी. सी. महालनोबिस हैं।
    (ii) मिश्रित कीमत क्रियाविधि में बुनियादी निर्णय बाज़ार द्वारा, जबकि गौण निर्णय प्रशासनिक शक्तियों द्वारा लिये जाते हैं।
    (iii) भारत में 1950-1991 तक मिश्रित कीमत क्रियाविधि लागू थी।

    उपरोक्त कथन में से कौन-सा/से सत्य नहीं है/हैं?
    (a) केवल (i) और (ii)
    (b) केवल (ii) और (iii)
    (c) (i), (ii) और (iii)
    (d) उपरोक्त में से कोई नहीं।

17. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) उत्पादन के सापेक्ष मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लागत प्रेरित कीमत वृद्धि का कारण हो सकता है।
    (ii) लागतजन्य मुद्रास्फीति उपभोक्ताओं के लिये श्रेयस्कर होते हैं।
    उपरोक्त कथन में कौन-सा/से सही है/हैं?
    (a) केवल (i)
    (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों
    (d) न तो (i) और न ही (ii)

18. निम्न कथनों पर विचार कीजिये-
    (i) विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में बाज़ार कीमत क्रियाविधि प्रचलित है।
    (ii) नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है।
    (iii) प्राथमिक वस्तुओं में परिवर्तन से नई वस्तुओं का उत्पादन द्वितीयक क्षेत्र करता है, जैसे-खनन एवं उत्खनन।
    उपरोक्त में सत्य कथन है/हैं-
    (a) केवल (ii)
    (b) केवल (iii)
    (c) केवल (i) और (ii)
    (d) (i), (ii) और (iii)

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच मुक्त सौदेबाजी के आधार पर निर्णय लेने की पद्धति को बाज़ार कीमत क्रियाविधि कहते हैं।
    (ii) बाज़ार कीमत क्रियाविधि के अनुसार कार्यशील अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं।
    (iii) यदि क्रेताओं एवं विक्रेताओं को सौदेबाजी की कोई स्वतंत्रता न हो, तो निर्णय की इस पद्धति को प्रशासित कीमत क्रियाविधि कहते हैं।
    उपरोक्त कथनों में सत्य है/हैं–
    (a) केवल (i) और (ii)
    (b) केवल (ii) और (iii)
    (c) केवल (i) और (iii)
    (d) (i), (ii) और (iii)

20. मिश्रित कीमत क्रियाविधि के संबंध में सत्य है/हैं–
    (i) इस क्रियाविधि में बुनियादी निर्णय प्रशासनिक शक्तियों द्वारा तथा गौण निर्णय बाज़ार द्वारा लिये जाते हैं।
    (ii) इसमें कुछ आर्थिक क्रियाकलाप पर सरकार की तो कुछ पर निजी संस्थाओं का अधिकार होता है।
    (iii) इस क्रियाविधि में लाइसेंसिंग की प्रक्रिया चयनात्मक होती है।
    कुट:
    (a) केवल (i) और (ii)
    (b) केवल (ii) और (iii)
    (c) केवल (i) और (iii)
    (d) (i), (ii) और (iii)

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखकर ही निर्णय लिये जाते हैं।
    (ii) समाजवाद में संपत्ति का अधिकार किसी भी तरीके से नहीं होता, लेकिन हमारे संविधान में संपत्ति का अधिकार अभी भी कानूनी है।
    उपरोक्त कथनों में कौन-सा/से सत्य है/हैं?
    (a) केवल (i)
    (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों
    (d) न तो (i) और न ही (ii)

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) कीमत विचलन के ऊपरिमुखी (Upward) प्रवृत्ति को मुद्रास्फीति जबकि अधोमुखी (Downward) को अवस्फीति कहते हैं।
    (ii) सरकार की आय प्राप्ति के सापेक्ष उच्चतर व्यय, मांग प्रेरित महँगाई का कारण है।
    उपरोक्त कथनों में असत्य है/हैं–
    (a) केवल (i)
    (b) केवल (ii)
    (c) (i) और (ii) दोनों
    (d) न तो (i) और न ही (ii)

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:
    (i) एक अनुमान के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में कानूनी अर्थव्यवस्था 2/3 है तथा 1/3 अर्थव्यवस्था गैर-कानूनी है।

(ii) समानांतर अर्थव्यवस्था से अभिप्राय काले धंधे एवं काले आय से संचालित अर्थव्यवस्था से है।

उपरोक्त कथनों में असत्य है/हैं–

(a) केवल (i) (b) केवल (ii)

(c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

24. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये

(i) यदि मांग के सापेक्ष आपूर्ति अधिक हो या आपूर्ति के सापेक्ष मांग कम हो तो अवस्फीति (Deflation) उत्पन्न होती है।

(ii) यदि उत्पादकों के बीच स्पर्द्धा अधिक हो तो कीमतें गिर जाती हैं।

(iii) यदि सरकार टैक्स अवकाश की घोषणा करे तो भी अवस्फीति उत्पन्न हो सकती है।

उपरोक्त कथनों में सत्य है/हैं–

(a) केवल (i) और (ii)

(b) केवल (ii) और (iii)

(c) केवल (i) और (iii)

(d) (i), (ii) और (iii)

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

(i) सकल घरेलू निवेश (Gross Domestic Investment) से आशय पैसे को उदासीन रखने की बजाय उत्पादन कार्य में निवेश किये जाने से है।

(ii) देश में घरेलू बचत का मान सर्वाधिक है, उसके बाद क्रमशः निगम और सरकारी बचत आते हैं।

उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सत्य है/हैं–

(a) केवल (i) (b) केवल (ii)

(c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

26. निर्यात के फायदे और नुकसान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

(i) निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ता है।

(ii) निर्यात बढ़ने से विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा, जिसकी परिणति घरेलू मुद्रा की मात्रा बढ़ने में होगी और इस प्रकार महँगाई बढ़ेगी।

उपरोक्त कथनों में कौन सा/से सत्य है/हैं–

(a) केवल (i) (b) केवल (ii)

(c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)

27. आयात बढ़ाने के फायदे और नुकसान के संदर्भ में सत्य है/हैं–

(i) जिन वस्तुओं का उत्पादन देश में नहीं होता, उनका आयात करने से देश का उत्पादन बढ़ेगा व देश का उपभोग स्तर उन्नत होगा।

(ii) आयात उदारीकरण से अन्तर्राष्ट्रीय निर्भरता बढ़ेगी जो भारत के बाह्य संप्रभुता के लिये दबाव उत्पन्न करेगा।

(iii) आयात बढ़ाने से विदेशी मुद्रा भंडार में कमी आएगी।

कूट:

(a) केवल (i) और (ii)

(b) केवल (ii) और (iii)

(c) केवल (i) और (iii)

(d) (i), (ii) और (iii)

28. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

(i) देशी बचत राशि का विदेशों में निवेश बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश कहलाता है।

(ii) बाह्योन्मुखी विदेशी निवेश से देश को कूटनीतिक फायदा होता है क्योंकि साझेदार देश में उत्पादन और रोज़गार बढ़ाने में मदद मिलती है।

उपरोक्त कथनों में असत्य है/हैं–

(a) केवल (i) (b) केवल (ii)

(c) (i) और (ii) दोनों (d) न तो (i) और न ही (ii)